श्री मधु लिमये : वहां की विधान सभा कहां है ? केरल में केन्द्रीय शासन चल रहा है, वर्ना मैं यह सवाल न उठाता ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मिनिस्टर साहब को कह दिया है कि वह इन्फर्मेशन ले कर दे दें । इस से ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : जिस कम्पनी से मजदूरों का झगड़ा चल रहा है, उस के मालिकों के द्वारा मजदूर कल्याण के सब कानूनों का अनेकों बार उल्लंघन किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को उन के बारे में सूचना मिली है और उस ने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : मैंने कहा है कि एक दफ़ा कानसिलियेशन हुआ था । उस के बाद कुछ झगड़ा हुआ । उस के बारे में हम ने फिर चीफ़ लेबर कमिश्नर को कहा कि वह कानसिलियेशन प्रोसीडिंग्ज शुरू करें और देखें कि क्या हो सकता है । मैंने चीफ़ सेक्रेट्री को भी लिखा है । कानून का जो उल्लंघन हुआ है, उस के बारे में लेबर लाज के मुताबिक कार्यवाही होगी ।

Shri A. P. Sharma: From the statement it appears that these people were arrested because they entered this protected area without permission. May I know whether this was the only reason or there was any other special reason like violent and other activities?

Shri Hathi: No other reason.

श्री बागड़ी : मंत्री महोदय ने कहा है कि हम ने लेबर कमिश्नर को लिखा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि लेबर कमिश्नर को कब लिखा गया है और अब तक उस का उत्तर न आने का क्या कारण है ?

श्री हाथी : उत्तर नहीं आया है और लिखा भी नहीं है । जब श्री वासुदेवन नायर और श्री वार्ष्णेय ने बताया, तब मैंने इस के बारे में दिल्ली के चीफ़ लेबर कमिश्नर को कहा । उन्होंने वहां टेलीफ़ोन किया । मैं ने भी टेलीफोन किया । कानसिलियेशन मीटिंग हो रही है । परसों तक की इन्फर्मेशन का मुझे पता है । उसके बाद का मुझे पता नहीं है ।

विदेशी पत्रिकाओं द्वारा भारत विरोधी प्रचार

*716. **श्री मधु लिमये** :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती रेणुका बड़फटकी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "टाइम्स" और "न्यूज वीक" पत्रिकायें भारतविरोधी प्रचार करती हैं;

(ख) क्या इन पत्रिकाओं ने भारत-पाकिस्तान युद्ध के लिये भारत को दोषी ठहराया है; और

(ग) क्या सरकार इन पत्रिकाओं तथा अन्य भारत विरोधी विदेशी पत्रिकाओं के भारत में आने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). अभी हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान इन पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ टिप्पणियां उचित तथा तथ्य-परक नहीं थीं ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई विशेष सुझाव सरकार के विचाराधीन नहीं है । सदन को ज्ञात ही है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है और इसलिये कुछ हद तक आलोचना को सहना ही पड़ता है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इन दो अमरीकी साप्ताहिकों में जो भारत विरोधी प्रचार किया गया है, उस को मैं पढ़ तो नहीं रहा हूं, लेकिन संक्षेप में बताना चाहता हूं । एक तो कहा गया कि काश्मीर के सम्बन्ध में भारत ने बादाफरामोशी की । फिर कहा गया कि अमरीकी पैटन टैंक और सेबर जेट के सामने हिन्दुस्तान की सेना और हिन्दुस्तान का हवाई दल तितर-बितर हो कर भाग गया । फिर कहा गया कि भारत ने भी अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ़ किया । फिर कहा गया कि ये ग़रीब भिखमंगे देश में, लेकिन हथियारों पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं । साथ साथ यह भी गहा गया है न्यूज वीक में कि हिन्दुस्तान ने कारगिल और हाजी पीर इलाके में प्रथम आक्रमण कर के पाकिस्तान को उकसाया और पाकिस्तान ने जो हमला किया, वह केवल प्रतिक्रिया के रूप में था । पिछली बार मंत्री महोदय ने इस सिद्धान्त को मान लिया कि दिमाग के लिए, विचारों के लिए जो खाद्य है पुस्तकें आदि, हम उन की छूट देंगे । लेकिन ये तो जहरीला प्रचार करने वाले साप्ताहिक हैं, जो खासकर हिन्दुस्तान, एशिया और अफ्रीका के काले लोगों के बारे में हमेशा गन्दी और झूठी बातें लिखते हैं । ये कोई पुस्तकें नहीं हैं और न ही दिमाग के लिए कोई खाद्य हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सारे भारत-विरोधी प्रचार को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार इन साप्ताहिकों पर पाबन्दी लगाने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को कई बार यह कहने की कोशिश की कि उनका हवाल इतना लम्बा हो रहा है कि मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता । लेकिन जब उन्होंने उस को पूरा कर लिया है, तो अगर मैं उस को डिसएलाउ करता हूं, तो माननीय सदस्य को शिकायत होगी ।

श्री ल० ना० मिश्र : उन साप्ताहिकों में जो बातें कही गई, उन को इस सदन में कह कर माननीय सदस्य ने उन के विचारों का यहां प्रचार किया है । जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है, अभी इन पत्रिकाओं पर पाबन्दी लगाने का विचार नहीं है । लेकन हमने इस बारे में जो कार्यवाही की है, वह मैं बताना चाहता हूं । यहां पर इन दोनों अखबारों के जो प्रतिनिधि हैं, उन को बुला कर यह कहा गया कि वे जिस तरह की सामग्री यहां से भेज रहे हैं, सरकार को वह पसन्द नहीं है । इस के अतिरिक्त हम ने वाशिंगटन में अपने राजदूत को कहा है कि वह टाइम और लाइफ़ इन्टरनेशनल के पब्लिशर्ज से बात करें, उन का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और उनको बतायें कि यह बात उचित नहीं है । अब तक ये दो काम किये गए हैं । आप ने यह देखा होगा कि उन का रवैया पहले से अच्छा है ।

श्री मधु लिमये : न्यूज वीक के किसी प्रतिनिधि का हमारे रेडियो पर भाषण प्रसारित हुआ था । क्या वह केवल हिन्दुस्तान के 48 करोड़ लोगों के लिए हुआ था या न्यूजवीक में उसी तरह का खुलासा छाप कर अमरीकी जनता के मन में जो भ्रम पैदा किया गया है, उसकी भी सफाई करने के विचार से हुआ था ? इसके बारे में भी क्या कुछ हमारी ओर से कहा गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे तो रेडियो भाषण का पता नहीं है । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं । न्यूज़वीक का जहां तक सवाल है उसके जो प्रधान सम्पादक हैं उन्होंने 23–24 मार्च 1965 को न्यू यार्क में एक ब्राडकास्ट किया था जिस में कि हमारा जो रुख है काश्मीर के मामले में, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े में, उसका उन्होंने समर्थन किया था और कहा था कि भारत का जो स्टैंड है इस मामले में वह सही है । उसका हमने यहां भारतीय रेडियो से भी प्रचार करवाया और उसको छपवा करके भी बटवा दिया ।

श्री बागड़ी : जो विदेशी अखबार जानबूझ कर भारत के खिलाफ दुश्मनाना प्रचार करते हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या सरकार के पास कोई अधिकार है या नहीं है, अगर है तो जो कुछ इन विदेशी पत्रकारों के किया है, उस अधिकार का उनके खिलाफ क्या इस्तेमाल किया गया है और यदि नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : सरकार के पास अधिकार तो अवश्य है और वह इस सदन द्वारा दिया गया अधिकार है । हमने करीब 49 अखबारों और किताबों के ऊपर इस अधिकार के अनुसार कार्रवाई भी की है । लेकिन जहां तक इन अखबारों का सवाल है, हमने कहा है कि हम लोगों को दुख है और हमने अपनी नाराजगी भी इन दोनों अखबारों के प्रतिनिधियों के साथ जाहिर की थी और कहा था उन से कि वे गलत काम कर रहे हैं। हमने कहा कि अच्छा हो यदि वे निष्पक्ष हो कर चीजों को छापें । यह सही है कि उनको स्वतंत्रता है लेकिन हमारी भी अपने लोगों के प्रति जवाबदेही है । और जैसा मैंने कहा है कि उनके रुख में तबदीली भी आई थी ।

श्री यशपाल सिंह : मंत्री महोदय ने फरमाया है कि हमारे यहां प्रेस की स्वतंत्रता है । हमने अपनी प्रेस को ही जैनुइन क्रिटिसिज्म की स्वतंत्रता दे रखी है या विदेशी पत्रकारों को भी सब प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है कि वे हमारे खिलाफ जहर बरसायें ? आखिर ये जो पत्र हैं ये आसमान से थोड़े ही बरसते हैं, आपके थ्रू ही तो आते हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने कहा तो है कि उन्होंने जो कुछ काम किया है, वह सही नहीं किया है । अच्छा काम उन्होंने नहीं किया है, गलत काम किया है । यह सही है कि जो विदेशी पत्रकार हैं और जो भारतीय पत्रकार हैं उन दोनों पर प्रिवेंशन आफ इंडिया रूल्स की प्राविजंस और एमरजेंसी की प्राविजंस समान रूप से लागू होती हैं । दोनों में कोई फर्क नहीं है । लेकिन जैसा मैंने कहा थोड़े दिनों तक हम देखना चाहते थे और हम चाहते थे कि वे अपने आप को सम्भाल लें तो अच्छा हो ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : आपने इस तरह की कितनी पत्रिकायें पकड़ी हैं जो भारत के विरुद्ध प्रचार कर रही थीं, कितनी पर आपने प्रतिबन्ध लगाया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने बताया तो है कि 49 । अगर नाम बताऊं तो बहुत बड़ा ब्योरा हो जायेगा । मैं टेबुल पर रख दूंगा ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : विदेशी पत्रिकाओं का ब्योरा दे दीजिये, दो-चार जो खास-खास है उनके नाम बता दीजिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : यह लिस्ट बहुत लम्बी है । एक इस में पेकिंग रिव्यू है एक चाइनीज रिव्यू है, पाकिस्तान के बहुत से अखबार हैं । इस तरह 49 की फेहरिस्त हमारे पास है ।

श्री रामसेवक यादव : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह आया है कि भारत के खिलाफ जो प्रचार चलता है वह पूरे देश के खिलाफ ही नहीं बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि इस सदन के माननीय सदस्य डा० राम

मनोहर लोहिया के खिलाफ भी फूलपुर के उपचुनाव के सिलसिले को लेकर एक चार सौ शब्दों का आर्टिकल छपा था जिस में सात गलतियां थीं ? इस तरह की चीज भी क्या सरकार के ध्यान में आई है और यदि आई है तो इसके बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सूचना मुझे जाननीय सदस्य से मिल रही है । इसका मुझे पता नहीं है ।

Shrimati Lakshmikanthamma: May I know whether the American Government allow the free circulation of such of our papers which criticise their policies?

Shri L. N. Mishra: I have no special information, but my impression is that in America they are allowed free circulation.

श्री किशन पटनायक : भारत विरोधी प्रचार दो प्रकार का होता है । एक तो भारत विरोधी रायों को प्रकाशित करना और दूसरे भारत के बारे में गलत, झूठी और गंदी खबरों को, तथ्यों को प्रकाशित करना । इस फर्क को समझते हुए क्या सरकार ऐसी पत्रिकाओं पर पाबंदी लगाने की बात सोच रही है जिन पत्रिकाओं में गलत और गन्दे तथ्यों को प्रकाशित किया जाता है और इन पत्रिकाओं पर नहीं जोकि भारत विरोधी राय कोई छपती हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने कहा तो है कि गलत बात नहीं होनी चाहिये । हमने अभी तक बरदाश्त किया लेकिन बरदाश्त करने की भी एक सीमा होती है । उस सीमा के बाहर कोई चला जाएगा तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी ।

श्री ह्रा० ना० तिवारी : मूल प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बहुत खतरनाक वक्तव्य दिया है । उन्होंने कहा है कि हमने अखबारों को स्वतंत्रता दे रखी है कि जो मन में आए छापें, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में या देश संबंधी मामलों में । किसी दुश्मन देश के साथ जब हमारी लड़ाई होती है उसके संबंध में जो मन में आये छापने की क्या उन्होंने अखबारों को स्वतंत्रता दे रखी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने कभी नहीं कहा है कि उनको स्वतंत्रता दे रखी है कि जो मन में आये छापे। मैंने कहा है कि प्रेस की हमारी देश में स्वतंत्रता है, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है । विरोधी दल के लोग तो बहुत हल्ला करते हैं कि ज्यादा स्वतंत्रता प्रेस को दो । जम्हूरियत की कुछ कीमत होती है जो देनी पड़ती है : की प्रैस के हिसाब से यह किया है ।

Shri S. M. Banerjee: I would like to know whether it has been brought to the notice of the hon. Miinster that not only have they distorted the news but they have also said that whenever the Defence Minister announces anything in the Lok Sabha people go on clapping without knowing that once the invincible Patton tanks advance from the Pakistan side India will have nothing but a defeat. Even such statements were issued by some newspapers. If so, I want to know whether these things have been contradicted and those newspapers have been proscribed and banned for circulation. They have been put to fire by the Army men.

Shri L. N. Mishra: I have already explained what we have done so far. Apart from that, the hon. Member must be aware of the fact that there was popular resentment against these two magazines in India.

Shri S. M. Banerjee: Why do you not ban them?

Shri L. N. Mishra: Quite a large number of them were burnt by the Indian people. That had a reaction in America and these two papers did improve subsequently.

Shrimati Lakshmikanthamma: Excuse me, Sir....

Mr. Speaker: I have already given her a chance.

Shrimati Lakshmikanthamma: I am not asking a question.

Mr. Speaker: No. Shri P. C. Borooah.

Shri P. C. Borooah: May I know whether Government's attention has been drawn to the deliberate distortion of reports by this section of the press to the effect that there were as many casualties on the Delhi roads during the black-outs as on the fighting front; if so, whether Government have banned the circulation of this particular issue of the paper?

Shri L. M. Mishra: We have seen all these reports. We are unnecessarily giving publicity to what appears in the press.

Shri Indrajit Gupta: May I draw the Minister's attention to a report which appeared in the Calcutta *Statesman* of 8th October which says that copies of *Newsweek*, an American Weekly, which arrived in Calcutta by air for sale were detained by the customs officials at Dum Dum because the Weekly was alleged to contain an article likely to encourage communal and anti-Indian sentiments? I want to know why this particular issue, which was detained on these grounds by the customs officials, was subsequently released and was allowed to be sold freely and distributed in this country?

Shri L. N. Mishra: I am not aware of this particular question. I require notice for this.

Shri Kapur Singh: Do Government regard every utterance not applauding Government's action and policy as anti-Indian; if not, who is to judge the matter and how?

Shri L. N. Mishra: The people at large, the democracy itself, will judge.

Mr. Speaker: Next question. Shri Yashpal Singh.

डा० राम मनोहर लोहिया : एक सवाल मुझे कर लेने दें ।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम सब से पहले था और मैंने आपको सब से पहले बुलाया था । लेकिन आप मौजूद नहीं थे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : इतना अफसोस है मुझ को कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं । मगर एक . . .

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मजबूर हूं । दूसरे सवाल पर जब मैं चला जाता हूं तो कभी मैंने ऐसा नहीं किया है । अगर आप करायें तो यह सारा डिपारचर हो जाएगा उससे ।

Stagnation in Assistants' and Clerks' Grades in the Central Sectt.

+

*717. **Shri S. M. Banerjee:**
Shri Yashpal Singh:
Shri Kapur Singh:
Shri Warior:
Shri Daji:
Shri Eswara Reddy:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Assistants, Upper Division Clerks and Lower Division Clerks with more than 10 years of service in that grade have not yet been promoted in the Central Secretariat;

(b) if so, whether stagnation in their grades is the maximum; and

(c) the steps taken by Government to remove the hardship experienced by those Assistants and Clerks?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The total strength of the grades of Assistant, U.D.C. and L.D.C. in the Secretariat and attached offices is as follows:—

Assistants	5,500 (approx)
Upper Division Clerks	3,000 (-do-)
Lower Division Clerks	10,000 (-do-)

Appointments to the various grades of the Central Secretariat Services are